Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/236
Peer Reviewed & Refereed Journal, JULY-AUG 2024, Vol- 13/84

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा पर एन. ई. पी. 2020 के प्रभाव (भरतपुर जनपद के विशेष संदर्भ में)

ध्रुव कुमार शर्मा
शोध–छात्र, संस्कृति विश्व विद्यालय, मथुरा
डॉ. मृत्युंजय मिश्रा
(शोध निर्देशक), शिक्षा विभाग, संस्कृति विश्व विद्यालय, मथुरा, उ0 प्र0

Paper Received On: 20 July 2024
Peer Reviewed On: 24 August 2024
Published On: 01 September 2024

Abstract

माध्यमिक स्तरपर संचार एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में आशातीत प्रतिफल के लिये तकनीकि शिक्षकों की सरकारी स्तर पर नियुक्ति एवं संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। अभिभावकों का अभिमत है कि शोध क्षेत्र के माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन शासकीय मानकों के अनुरूप हो रहा है। ग्रामीण व शहरी माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव में सार्थक अन्तर है। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन शासकीय मानको के अनुरूप हो रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 में समाहित मल्टी डिसिप्लिनरी एप्रोच के द्वारा स्किल डवलपमेंण्ट का प्रयास किया जाना प्रमुख लक्ष्य है। क्योंकि यह एक दीर्घ कालिक प्रकिया है, जिसका वर्तमान में तात्कालिक प्रभाव पूर्णतः परिलक्षित नहीं है। परन्तु भविष्य में इसके कियान्वयन के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना है।

पारिभाषिक शब्दावली : माध्यमिक विद्यालय, शैक्षिक समस्यायें, संसाधन, वित्तपोषण।

शोध समस्या में आने वाले प्रत्येक शब्द का शोध के अनुक्रम में परिभाषीकरण शोधार्थी ने निम्न प्रकार से किया है–

1. माध्यमिक शिक्षा स्तर – कक्षा 9 से 10 तक की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा स्तर कहा जाता है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (rashtriya shiksha niti 1986) में शिक्षा को भारत की वर्तमान स्थितियों एवं

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आदर्शों के अनुसार बनाया गया। जिसके द्वारा छात्रों में लोकतंत्र के प्रति आदर्श भावना का निर्माण करने एवं लोकतंत्र के प्रति आस्था भाव का विकास करने जैसे विचारों को सम्मिलित किया गया। इसके द्वारा छात्रों को वास्तविक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं का निर्धारण किया गया। जिससे वह अपने भावी जीवन मे जीविकोपार्जन कर सकें एवं समाज मे सम्मानपूर्वक रह सकें।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – शिक्षा के क्षेत्र में सतत् विकास के लक्ष्यों के अनुरूप सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है।
4. प्रावधान – इसका आशय माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शासन द्वारा लागू एकीकृत शिक्षा योजना 1986 एवं 2020 के प्रावधानों से है।

विवेचना एवं परिलब्धियाँः

प्रस्तुत अध्ययन भारत के राजस्थान राज्य के जनपद भरतपुर के माध्यमिक विद्यालयों के सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण में सूचनादाताओं के रूप में 100 शिक्षक, 100 छात्र एवं 100 अभिभवकों का चयन किया गया है।

भारतवर्ष की स्वतंत्रता के पश्चात, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 (University Education Commission 1948) जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 (Secondary Education Commission 1952) की स्थापना हुई। इस प्रकार इन आयोगों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए एक नीति प्रस्तावित की थी। जिसे भारतीय शिक्षा नीति 1968 के नाम से जाना जाता है। इसे लागू किया गया किन्तु यह ठीक प्रकार से कार्यन्वित न हो पायी और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभिन्न प्रकार के दोष पाए गए। अतः इन आयोगों ने भारतीय शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उसे बनाने के लिए प्रयास किए और अगस्त 1985 में भारत सरकार के द्वारा एक परिपत्र शिक्षा में चुनौती प्रस्तुत किया गया। जिसमें कहा गया था, कि कोई भी शिक्षा नीति तब तक सफल नहीं हो सकती है,

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जब तक उस शिक्षा नीति को अच्छी तरह से ठोस रूप से क्रियान्वित ना किया जाए। इस विषय पर विभिन्न प्रकार की सभाएँ तथा वाद विवाद हुए जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान आयोग (University Education Grants Commission) तथा अन्य शिक्षा से जुड़े हुए संगठनों ने विचार विमर्श करके एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की जिसे 1986 में संसद (Parliament) में पेश कर दिया गया।

21वीं सदी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जुलाई 2020 में हुआ और यह नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिये नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित योजना में, सर्व शिक्षा अभियान (एस. एस. ए.), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए) और शिक्षक शिक्षण अभियान को समाहित कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) - 3 साल का प्री–प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2. तीन वर्ष की प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage) तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण – ग्रेड 6, 7, 8 और 4 वर्ष का उच्च (माध्यमिक) चरण – ग्रेड 9, 10, 11, 12।

NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा – 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। NEP 2020 नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिये समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना तथा एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर विशेष बल दिया गया है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अध्ययन के उपरान्त चयनित शोध "माध्यमिक शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का प्रभाव शीर्षक पर अध्ययन" भरतपुर जनपद (राजस्थान) के सन्दर्भ में निष्कर्षों को इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है–

• शोध क्षेत्र के 90.00 प्रतिशत शिक्षक/प्राचार्यो एवं 70.00 प्रतिशत अभिभावकों का अभिमत है कि माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन शासकीय मानकों के अनुरूप हो रहा है।

• शोध क्षेत्र के 90.00 प्रतिशत शिक्षकों का अभिमत है कि माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन शासकीय मानकों के अनुरूप हो रहा है।

• न्यादर्श में चयनित शिक्षक/प्राचार्यो में से 95.00 प्रतिशत का अभिमत है कि माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिणामस्वरूप नामांकन दर में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शत–प्रतिशत सूचनादाताओं का वक्त्व्य है कि शोध क्षेत्र के माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप शालात्यागी दर घट रही है।

• शोध क्षेत्र के 80.00 प्रतिशत शिक्षकों का अभिमत है कि माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप शालात्यागी दर घट रही है।

• शोध क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के शालात्यागी दर में कोई सार्थक अन्तर नही है। ग्रामीण व शहरी माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव में सार्थक अन्तर है। 80.00 प्रतिशत माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा के क्रियान्वयन के फलस्वरूप विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिरुचि में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

• 80.00 प्रतिशत शिक्षकों/प्राचार्यो का अभिमत है कि माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में वृद्धि हेतु शासकीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है।

• सूचनादाताओं का अभिमत है कि नई शिक्षानीति 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी एप्रोच के द्वारा स्किल डवलपमेंण्ट का प्रयास किया जा रहा है ,

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

परन्तु माधमिक विद्यालयों में संसाधनों का अभाव, निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग की प्रमुख बाधा है।

समस्याएँ एवं अवरोध : किसी भी कार्य का सफलतापूर्वक संपादन यह इंगित करता है कि व्यक्ति ने अपने द्वारा निर्धारित किये गये उद्देश्यों की प्राप्ति कर लिया है। साथ ही उसने अपने कार्य का सम्पादन बहुत निष्ठा एवं रुचिपूर्वक किया है। जिसमें व्यक्ति ने कार्य किया, परन्तु कई बार व्यक्ति जिसका सम्पादन वह सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है, जिसके कई कारण उत्तरदायी होता है जैसे उसका नियोजन किस प्रकार का था, उसकी रुचि तथा निष्ठा जैसे आयामों का स्तर किस प्रकार का था। इसी के साथ–साथ कभी ऐसा भी होता है कि कार्य के मध्य में कुछ ऐसी घटनायें या बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिस कारण से उसका कार्य करना अवरुद्ध हो जाता है जो सफलता पूर्वक सम्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नानुसार है–

- शोध क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा नीति 2020 के संचालन को लेकर मत भिन्नता है।
- शोध क्षेत्र में स्थित कुछ माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव है।
- शोध क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों में शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले शैक्षिक तकनीकी के संसाधन एवं शिक्षण हेतु सहायक शिक्षण सामग्री पर्याप्त नहीं है।
- शोध क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में वृद्धि हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं।

सुझाव : समस्याओं एवं अवरोध का निराकरण करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए –

- शोध क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया जाय।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों का ठीक से संचालन के लिये शिक्षकों को समय – समय पर उचित प्रशिक्षण पदान किया जाये।
- माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों के उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार कर शाला अप्रवेशी बालक–बालिकाओं के शाला प्रवेश पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।
- माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित की जाय।
- शिक्षकों को शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक दशा एवं स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- छात्रों की रुचि, अभिप्रेरणा तथा कठिनाई निवारण का विशेष ध्यान रखा जाय तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर तथा क्रिया आधारित बनाने का प्रयास करें।
- विद्यालयों के अभिलेखों का निर्धारित समय पर निरीक्षण किया जाय।
- जिला स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की नियमित मानीटरिंग हो।
- प्रशिक्षण तथा मानीटरिंग को एक नियमित प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाय।

भावी शोध हेतु सुझाव : भावी शोध की संभावनाएँ निम्नानुसार है–

- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का समीक्षात्मक अध्ययन।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों मे सामाजिक गुणों की विकासात्मक गतिविधियों से विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों एवं कर्तव्यों पर कोई सार्थक प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पाठ्य सहगामी गतिविधियों सें विद्यार्थियों की व्यवहारिक उपलब्धियो का तुलनात्मक अध्ययन।
- विद्यालयों में व्यक्तिगत गुणों की विकासात्मक गतिविधियों से विद्यार्थियों के व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- विद्यालयों में सामाजिक गुणों की विकासात्मक गतिविधियों से विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों एवं कर्तव्यों का समीक्षात्मक अध्ययन।

सन्दर्भ ग्रंन्थः

Singh S. D. (2006) : Indian Journal 07 Teacher Education. Vol-3, No-2 December-2006 pp-99. Gupta Suneeta (2008) : A Study of the Age of Entry of all Children in Standard-I. 6041 Children in 30 school in localities under survey. Primary Education Department.

Basu, A.N. (2008) : Education in mordren India Beset,

Agrawal B. (2003) : Research in Education

Sogarwal A. (2008): Teacher Role in the school guidance programme, Hand book of guidance and counseling, N.C.E.R.T. PP. 32-35.

Verma S.P. (2006) : India's Struggle to Universalize Elementry Education, M.D. Publication, Pvt. Ltd. New Delhi.

Singh, V.P. (2004) : General School Education in India and Development There of Journal of Indian Education, 30 (1): pp 59-75.

बन्दोपाध्याय ए. (2002) : शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies